ई संदेश

9 अप्रैल 2026 | अंक 200

सात दिन-सात पृष्ठ

- वैश्विक निवेश का नया केंद्र बनता उत्तर प्रदेश: सिंगापुर के साथ औद्योगिक और सांस्कृतिक साझेदारी को मिली नई गति
- आकाशवाणी: जनविश्वास और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त स्वर
- सुरक्षित प्रदेश, सशक्त पुलिस: 81 हजार नई भर्तियों से सुदृढ़ होगी कानून-व्यवस्था
- शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण का आधार हर बच्चा स्कूल जाए: मुख्यमंत्री
- रंगमंच समाज का दर्पण, जन-चेतना और राष्ट्रभक्ति का सशक्त माध्यम: मुख्यमंत्री
- बदलता गोरखपुर: विरासत का सम्मान और विकास की नई उड़ान
- शिक्षा, संस्कार और तकनीक का समन्वय: डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ते कदम
- लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष पत्रकारिता, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें मीडियाकर्मी: मुख्यमंत्री
- महिला आत्मनिर्भरता से सशक्त होगा राष्ट्र: दुग्ध क्रांति और विकास की नई राह पर आजमगढ़
- कृषि कायाकल्प से साकार होगा विकसित भारत का सपना: मुख्यमंत्री ने किया छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस का भव्य शुभारम्भ
- बुन्देलखण्ड में रक्षा विनिर्माण को लगेंगे पंख: चित्रकूट में राडार और वायु रक्षा प्रणालियाँ बनाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 07 अप्रैल, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

वैश्विक निवेश का नया केंद्र बनता उत्तर प्रदेश: सिंगापुर के साथ औद्योगिक और सांस्कृतिक साझेदारी को मिली नई गति

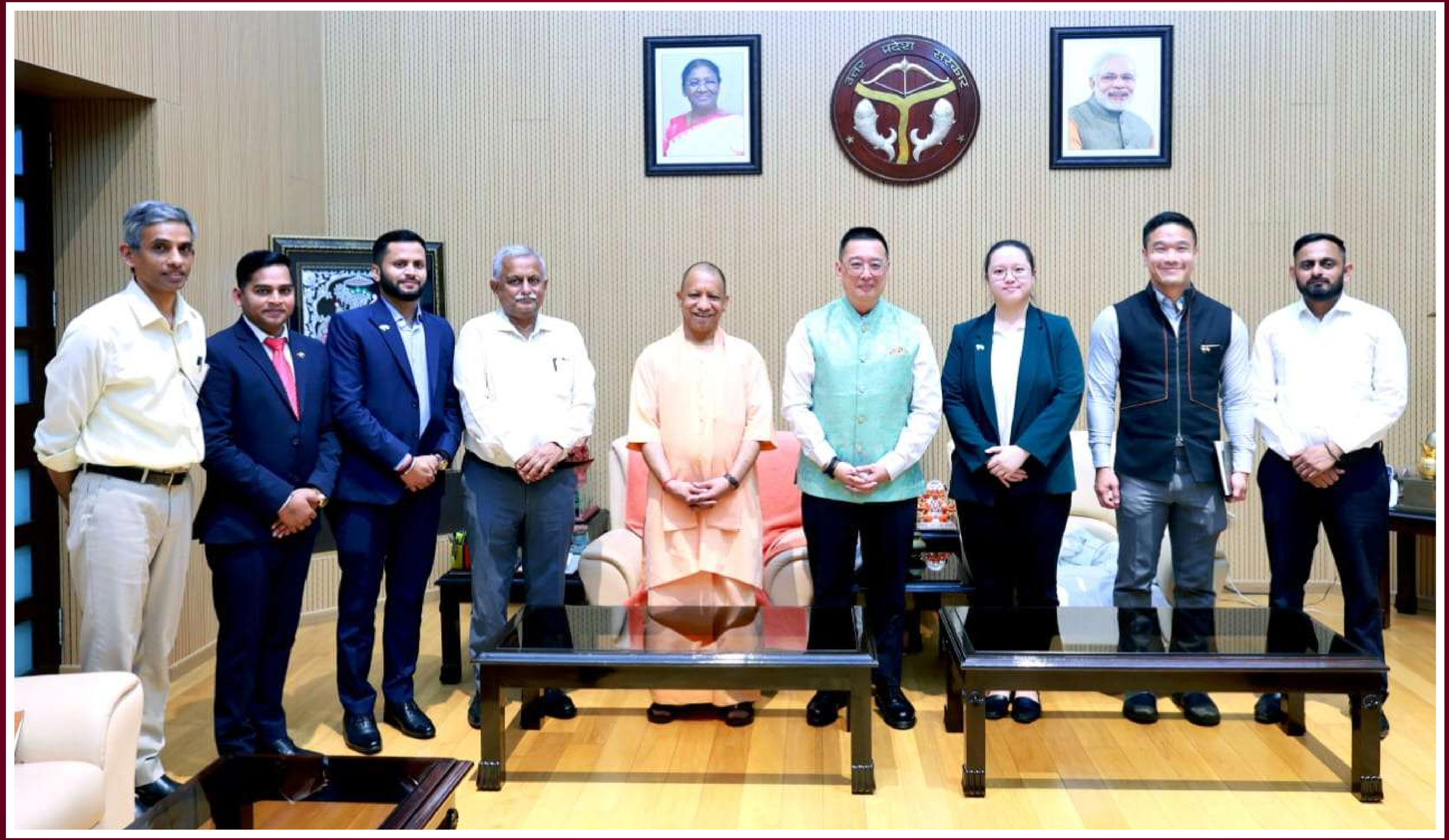

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की तेजी से बदलती आर्थिक तस्वीर और वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में इसकी बढ़ती साख ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता के नए द्वार खोल दिए हैं। इसी क्रम में 02 अप्रैल, 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सिंगापुर के उच्चायुक्त श्री साइमन वॉन्ग के बीच लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई शिष्टाचार भेंट ने राज्य के औद्योगिक भविष्य को एक नई और सकारात्मक दिशा प्रदान की है। इस उच्चस्तरीय बैठक में दोनों पक्षों के बीच निवेश, कौशल विकास, आधारभूत संरचना और सांस्कृतिक विरासत को साझा करने पर गहन मंथन हुआ, जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास दर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा के दौरान अत्यंत प्रभावी ढंग से यह स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश आज 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के मूल मंत्र पर चलते हुए देश की सबसे गतिशील और तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुका है। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक सुरक्षित, पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश की सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, आधुनिक कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस-वे का विशाल जाल और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आज उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की पहली पसंद बना रही हैं। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर को एक विश्वसनीय तकनीकी और आर्थिक साझेदार बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सिंगापुर की विशेषज्ञता और उत्तर प्रदेश की विशाल संभावनाओं का यह ऐतिहासिक मिलन सतत विकास, नवाचार और रोजगार सृजन के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

सिंगापुर के उच्चायुक्त श्री साइमन वॉन्ग ने मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों के दौरान प्रदेश में हुए प्रशासनिक, ढांचागत और औद्योगिक सुधारों की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से इस वर्ष फरवरी माह में मुख्यमंत्री की सफल सिंगापुर यात्रा का उल्लेख करते हुए बताया कि उस दौरे ने न केवल सिंगापुर, बल्कि संपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया के औद्योगिक जगत में उत्तर प्रदेश के प्रति एक सकारात्मक, स्थिर और भरोसेमंद छवि निर्मित की है। उच्चायुक्त ने यह महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की कि सिंगापुर की जो कंपनियां वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, वे यहाँ के निवेश अनुकूल माहौल से बेहद संतुष्ट हैं और अब अपने निवेश के विस्तार की सक्रिय योजना बना रही हैं।

सहयोग के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यह भी तय हुआ कि आगामी महीनों में सिंगापुर के औद्योगिक जगत का एक बड़ा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश का दौरा करेगा। यह दल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की जमीनी हकीकत का अवलोकन कर बड़े निवेश प्रस्तावों को मूर्त रूप देगा। केवल औद्योगिक निवेश ही नहीं, बल्कि युवाओं के कौशल विकास (स्किलिंग) पर भी दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण सहमति बनी है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक मोर्चे पर कुशीनगर और सारनाथ जैसे ऐतिहासिक बौद्ध पर्यटन स्थलों के विकास के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी साझा सहमति बनी। यह साझेदारी न केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा, बल्कि झांसी और वाराणसी जैसे शहरों के संतुलित एवं समावेशी विकास को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

आकाशवाणी:
जनविश्वास और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त स्वर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 02 अप्रैल, 2026 को राजधानी लखनऊ में आकाशवाणी लखनऊ के 89वें स्थापना दिवस और सांस्कृतिक संध्या समारोह में सहभागिता की। इस गौरवशाली अवसर पर मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कारों से अलंकृत विभूतियों एवं आकाशवाणी लखनऊ से जुड़े वरिष्ठ प्रसारकों को सम्मानित करते हुए आकाशवाणी को समाज को जोड़ने तथा भारत की आस्था को सम्मान देने का एक सशक्त माध्यम बताया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आकाशवाणी से प्रसारित समाचारों में गुणवत्ता, भाषा की शुद्धता और सत्यता की स्पष्ट झलक मिलती है, जिसने सदैव तथ्यों को उनके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करने का साहस दिखाया है। उन्होंने रेखांकित किया कि आकाशवाणी ने भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली और कुमांऊनी जैसी स्थानीय बोलियों के माध्यम से जन-जन को जोड़ने और लोक कलाओं के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह संस्थान 'आवाज से आगे बढ़कर जन विश्वास' का प्रतीक बन गया है।

मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक संदर्भों का स्मरण करते हुए बताया कि आकाशवाणी लखनऊ केंद्र का शुभारंभ 02 अप्रैल, 1938 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के प्रीमियर पंडित गोविंद बल्लभ पंत के कर-कमलों से हुआ था और इसकी पहली धुन 'वन्दे मातरम्' थी। अपनी 88 वर्षों की शानदार यात्रा में इस केंद्र ने संवाद की शक्ति को सुदूर गांवों तक पहुँचाया, जहाँ कभी अन्य माध्यमों की पहुँच नहीं थी। उन्होंने कहा कि सुबह के कार्यक्रमों में 'भरत चले चित्रकूट' की गूँज और समय-समय पर प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों ने पीत पत्रकारिता से मुक्त रहकर सूचना का प्रसार किया। मुख्यमंत्री ने आकाशवाणी को आजादी की लड़ाई से लेकर किसान दर्शन, स्थानीय लोक वाद्यों के संरक्षण और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'मन की बात' जैसे क्रांतिकारी कार्यक्रमों का साक्षी बताया। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि आपातकाल से लेकर श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के लाइव प्रसारण तक, आकाशवाणी देश की हर महत्वपूर्ण घटना का जीवंत दस्तावेज रहा है।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की उन महान विभूतियों को सम्मानित किया जिन्होंने विकसित भारत की संकल्पना में विशिष्ट योगदान दिया है। सम्मानित होने वालों में साहित्य के क्षेत्र से डॉ. विद्या विन्दु सिंह व श्री हृदय नारायण दीक्षित, चिकित्सा क्षेत्र से डॉ. मंसूर हसन, प्रो. सोनिया नित्यानंद, डॉ. आर.के. धीमन व डॉ. सुनील प्रधान, लोकगायन में श्रीमती मालिनी अवस्थी, रंगमंच में डॉ. अनिल रस्तोगी, पर्वतारोही सुश्री अरुणिमा सिन्हा और प्रगतिशील किसान श्री रामसरन वर्मा शामिल रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारकों श्री गुलाब चन्द्र, श्री सुशील रॉबर्ट बनर्जी, श्री सतीश कुमार ग्रोवर, श्री यज्ञदेव पंडित, श्री विजय कुमार बनर्जी, श्री रज्जन लाल, श्री नवनीत मिश्र, श्री हरीश सनवाल, श्री भोलानाथ और श्री केवल कुमार को भी उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि यह सम्मान प्रदेश की 25 करोड़ जनता का सम्मान है और आकाशवाणी की भूमिका भविष्य में भी समाज के हर तबके के लिए एक मार्गदर्शक मंच के रूप में बनी रहनी चाहिए।

सुरक्षित प्रदेश, सशक्त पुलिस:

81 हजार नई भर्तियों से सुदृढ़ होगी कानून-व्यवस्था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 02 अप्रैल, 2026 को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में पुलिस विभाग के विभिन्न प्रभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इस एक वर्ष में पुलिस के विभिन्न संवर्गों में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपनिरीक्षक, आरक्षी नागरिक पुलिस, रेडियो सहायक परिचालक और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित सभी श्रेणियों की ये भर्तियां पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्धारित समयसीमा के भीतर तकनीक आधारित प्रणाली से संपन्न कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि यह व्यापक अभियान न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि प्रदेश को एक अधिक सक्षम, ऊर्जावान और आधुनिक पुलिस बल भी उपलब्ध कराएगा।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए तकनीक और जवाबदेही पर विशेष बल दिया। पीआरवी-112 सेवा की कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हुए उन्होंने वर्तमान के 6 मिनट के औसत रिस्पांस टाइम को और कम करने तथा डेटा-आधारित पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स का संचालन इस प्रकार हो कि जनता में सुरक्षा का विश्वास और अपराधियों में कानून का भय बना रहे। इसी क्रम में उन्होंने राजधानी के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे जनभवन, मुख्यमंत्री आवास और पुलिस मुख्यालय पर लंबे समय से तैनात पुलिस कार्मिकों के स्थानांतरण के निर्देश देते हुए कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। अग्निशमन सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने 'एक तहसील-एक फायर टेंडर' के लक्ष्य को प्राथमिकता दी और प्रत्येक जनपद में कम से कम एक हाइड्रोलिक फायर टेंडर की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में साइबर सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर प्रहार को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साइबर क्राइम मुख्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित तकनीकी हस्तक्षेप से जनता के 425.7 करोड़ रुपये सुरक्षित बचाने और 1930 हेल्पलाइन की क्षमता में कई गुना वृद्धि किए जाने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने आमजन की मेहनत की कमाई की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए प्रदेश व्यापी साइबर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति स्पष्ट करते हुए उन्होंने सतर्कता अधिष्ठान को ट्रैप एवं सर्च की कार्रवाइयों में तेजी लाने को कहा। साथ ही, कारागारों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के विस्तार, नागरिक सुरक्षा इकाइयों के सुदृढ़ीकरण और राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत बच्चों को परिजनों से मिलाने जैसे मानवीय कार्यों को और गति देने पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने अंत में निर्देश दिया कि पुलिस प्रशिक्षण को आधुनिक, व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी बनाया जाए, जिससे विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप एक आदर्श सुरक्षा तंत्र स्थापित हो सके।

शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण का आधार
हर बच्चा स्कूल जाए: मुख्यमंत्री

वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 04 अप्रैल, 2026 को जनपद वाराणसी के शिवपुर स्थित कम्पोजिट विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 'स्कूल चलो अभियान' का भव्य शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य को संस्कारित करने और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा कि ईश्वर ने उन्हें देश के भविष्य को तराशने की पुनीत जिम्मेदारी दी है, जिसे पूरी ईमानदारी से निभाने पर ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बच्चों को नवीन सत्र की पाठ्य-पुस्तकें वितरित कीं, निपुण विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए और स्वयं बच्चों को मिड-डे-मील का भोजन परोसकर उनके उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने श्री काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन कर प्रदेश की समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री ने 15 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के प्रथम चरण और जुलाई में प्रस्तावित दूसरे चरण की सफलता के लिए शिक्षकों को घर-घर जाकर अभिभावकों से संवाद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विगत 09 वर्षों में लगभग 60 लाख नए बच्चों को बेसिक शिक्षा से जोड़ा गया है और अब लक्ष्य 'ड्रॉप आउट रेट' को 3 प्रतिशत से घटाकर शून्य पर लाना है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 'डबल इंजन' सरकार बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, जूते-मोजे और स्वेटर के लिए डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खातों में धनराशि भेज रही है। उन्होंने 'ऑपरेशन कायाकल्प' की सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश के 1.36 लाख से अधिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि वे अपने बच्चों को भी उन्हीं विद्यालयों में पढ़ाएंगे जहाँ वे कार्यरत हैं, तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होगी।

प्रदेश में शैक्षिक ढांचे को और अधिक सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 12वीं कक्षा तक उच्चीकृत हो गए हैं और प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 'मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय' स्थापित किए जा रहे हैं जहाँ प्री-प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध होगी। शिक्षकों के कल्याण की दिशा में कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपये और शिक्षामित्रों का मानदेय 18,000 रुपये इसी माह से लागू करने तथा सभी के लिए 5 लाख रुपये की 'कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा' की घोषणा की। उन्होंने अंत में कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए शिक्षा को एक जन-आंदोलन बनाना अनिवार्य है, जिसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर ग्राम प्रधानों तक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

रंगमंच समाज का दर्पण, जन-चेतना और राष्ट्रभक्ति का सशक्त माध्यम: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 05 अप्रैल, 2026 को राजधानी स्थित भारतेन्दु नाट्य अकादमी के 'स्वर्ण जयन्ती नाट्य समारोह' का भव्य शुभारम्भ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने 22 करोड़ रुपये की लागत से अकादमी भवन और दो प्रेक्षागृहों के जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण किया तथा अकादमी की पत्रिका 'रंगवेद' का विमोचन भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रंगमंच समाज का वह दर्पण है जो जन-चेतना को नई दिशा प्रदान करता है। उन्होंने अकादमी के पुराने विद्यार्थियों और वरिष्ठ रंगकर्मियों को सम्मानित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जब पुरातन और नवीन पीढ़ी मिलकर कार्य करेगी, तभी कला और संस्कृति के क्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने समारोह में मंचित नाटक 'आनन्दमठ' की सराहना करते हुए इसे राष्ट्रभक्ति का जीवंत दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय की यह कृति विदेशी हुकूमत की संवेदनहीनता और क्रूरता को उजागर करती है, जिसने अकाल जैसी त्रासदी में भी भारतीयों पर अत्याचार किए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 'वन्दे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति विभाग भारतेन्दु नाट्य अकादमी के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इस पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन कराएगा। उन्होंने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि एक संवेदनशील सरकार आपदा में नागरिकों के साथ खड़ी होती है, जबकि अतीत की विदेशी हुकूमत ने नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया था।

संस्कृति और इतिहास के पुनर्जागरण पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने अकादमी को महाराजा सुहेलदेव, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई और राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जैसे महापुरुषों के शौर्य पर आधारित नाट्य श्रृंखलाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारे नायकों के बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए संवाद, संगीत और प्रभावी अभिनय का समन्वय आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के योगदान को अविस्मरणीय बताते हुए काशी नागरी प्रचारिणी सभा के गौरव को पुनर्स्थापित करने और मातृभाषा हिन्दी की उन्नति के लिए सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही, उन्होंने अकादमी में विद्यार्थियों के प्रवेश की क्षमता बढ़ाने और छात्रावास निर्माण के प्रस्तावों को तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर ले जाने का आह्वान किया।

बदलता गोरखपुर:

विरासत का सम्मान और विकास की नई उड़ान

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 05 अप्रैल, 2026 को जनपद गोरखपुर के पाण्डेयहाता में 34 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने 29 करोड़ रुपये की लागत से ऐतिहासिक घंटाघर के जीर्णोद्धार कार्य, शहीद बंधु सिंह मल्टीलेवल पार्किंग और व्यावसायिक भवन का लोकार्पण भी किया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घंटाघर आजादी की लड़ाई का साक्षी रहा है और वर्तमान पीढ़ी का यह दायित्व है कि वह अपनी विरासत का पुनरुद्धार करे। उन्होंने शहीद बंधु सिंह और शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्तियों का अनावरण कर उन्हें भावांजलि अर्पित की और सामूहिक 'वन्दे मातरम्' गायन में सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व गोरखपुर की पहचान 'माफिया, मच्छर और इंसेफेलाइटिस' से होती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में यह शहर 'स्मार्ट सिटी' और विकास के मॉडल के रूप में उभरा है। उन्होंने बताया कि पाण्डेयहाता से धर्मशाला बाजार तक 'विरासत गलियारा' (Heritage Corridor) तैयार किया जा रहा है, जो जाम और जलभराव से मुक्त होकर सबसे सुंदर सड़क के रूप में विकसित होगा। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि सुरक्षित माहौल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से व्यापार सुगम हुआ है और अब 'गुण्डा टैक्स' का दौर समाप्त होकर निवेश का युग शुरू हो गया है। उन्होंने गीडा में हुए 15,000 करोड़ रुपये के निवेश और 50,000 युवाओं को मिले रोजगार का उल्लेख करते हुए इसे बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर बताया।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर अब चार विश्वविद्यालयों और तीन मेडिकल कॉलेजों के साथ शिक्षा का बड़ा केंद्र बन चुका है। उन्होंने एम्स, फर्टिलाइजर कारखाने के पुनर्संचालन, रामगढ़ ताल के सुंदरीकरण और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी परियोजनाओं को गोरखपुर की नई पहचान बताया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार अब गोरखपुर को 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित करने जा रही है, जिसके तहत चिलुआताल में 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने अंत में स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर कायम है, जहाँ माफिया मुक्त वातावरण में बेटियाँ और व्यापारी पूरी तरह सुरक्षित हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था तीन गुना बढ़कर 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार कर रही है।

शिक्षा, संस्कार और तकनीक का समन्वय: डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ते कदम

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 06 अप्रैल, 2026 को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के प्रतिष्ठित संस्थान दिग्विजयनाथ पी.जी. कॉलेज में नवनिर्मित आधुनिक कम्प्यूटर प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह प्रयोगशाला कॉलेज के पूर्व शिक्षक और 'बच्चा बाबू' के नाम से लोकप्रिय रहे डॉ. तेज प्रताप शाही की स्मृति में उनके परिवार द्वारा निर्मित कराई गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉ. शाही की स्मृतियों को नमन करते हुए उनके पुत्रों, श्री अनन्य प्रताप शाही और श्री अतिरेक शाही के इस पुनीत कार्य की सराहना की। मुख्यमंत्री ने डॉ. शाही के साथ अपने पुराने संस्मरणों को साझा करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और गोरक्षपीठ के प्रति उनकी अटूट निष्ठा व समर्पण को याद किया। उन्होंने कहा कि डॉ. शाही ने विपरीत परिस्थितियों में भी गोरक्षपीठ के मूल्यों और पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी के आदर्शों का साथ कभी नहीं छोड़ा, जो उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, शोध-अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में ऐसी प्रयोगशालाएं न केवल छात्रों के ज्ञानवर्धन का केंद्र बनेंगी, बल्कि उन्हें भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार कर स्वरोजगार और विकास के नए अवसरों से भी जोड़ेंगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि शिक्षा के साथ-साथ उच्च मूल्यों और संबंधों की मर्यादा को बनाए रखना ही वास्तविक व्यक्तित्व निर्माण है, जिसे डॉ. तेज प्रताप शाही ने अपने जीवन में चरितार्थ किया था।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आधुनिक भारत के निर्माण में तकनीकी शिक्षा की अपरिहार्यता पर चर्चा की और शिक्षकों व विद्यार्थियों को शोध कार्यों में नई ऊर्जा के साथ जुटने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेन्द्र सिंह, विधायक ऋषि त्रिपाठी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी तथा गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल एक तकनीकी सुविधा के विस्तार का साक्षी बना, बल्कि इसने गुरु-शिष्य परंपरा और पूर्वजों के प्रति सम्मान की गौरवशाली संस्कृति को भी पुनर्स्थापित किया।

लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष पत्रकारिता

राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें मीडियाकर्मी: मुख्यमंत्री

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 07 अप्रैल, 2026 को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होकर मीडिया जगत का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ने सदैव विपरीत परिस्थितियों में भी भारत और यहाँ के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, जहाँ स्वस्थ आलोचना का स्वागत है, बशर्ते उसे व्यक्तिगत रंजिश न माना जाए। मुख्यमंत्री ने हिन्दी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर को रेखांकित करते हुए 'उदन्त मार्तण्ड' से लेकर स्वाधीनता आंदोलन तक के गौरवशाली सफर का स्मरण किया। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि गोरखपुर प्रेस क्लब ने अपनी स्थापना के समय से ही पत्रकारिता के मूल्यों को बिना डिगे आगे बढ़ाया है, जो कि अत्यंत सराहनीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लगभग 3 करोड़ से अधिक आबादी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए गोरखपुर पर निर्भर है, ऐसे में यहाँ की पत्रकारिता की दिशा जनमानस में राष्ट्रभक्ति का भाव जगाने वाली होनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारिता के बदलते स्वरूपों—प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया—की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए कहा कि मीडिया को स्वयं को बेलगाम नहीं होने देना चाहिए, बल्कि इसे आचार संहिता और नैतिक मूल्यों के साथ समाज हित में कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की कि यदि सोशल और प्रिंट मीडिया के तथ्यों में भिन्नता होती है, तो इससे जनमानस विचलित होता है; अतः मीडिया के विभिन्न रूपों में परस्पर समन्वय होना अनिवार्य है। उन्होंने 'सत्यमेव जयते' के भाव को पत्रकारिता का मूल आधार बताते हुए विघटनकारी शक्तियों से विचलित न होने की प्रेरणा दी।

पत्रकारों के कल्याण की दिशा में मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ सदैव खड़ी है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के आवास के साथ-साथ पत्रकारों के लिए भी सस्ते आवास तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मीडियाकर्मी सुरक्षित और निश्चिंत होकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें।

इसके अतिरिक्त, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा और पहचान पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री ओंकार धर द्विवेदी और उनकी टीम को प्रमाण-पत्र प्रदान किए और विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्यकारिणी विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में अपनी महती भूमिका निभाएगी।

महिला आत्मनिर्भरता से सशक्त होगा राष्ट्र:
दुग्ध क्रांति और विकास की नई राह पर आजमगढ़

आजमगढ़: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 06 अप्रैल, 2026 को जनपद आजमगढ़ के ग्राम मिरिया रेहड़ा में 'श्री बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादक संस्था' के नवनिर्मित दुग्ध अवशीतन केन्द्र (चिलिंग प्लांट) का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला स्वावलंबन को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है, तो पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। मुख्यमंत्री ने 56 हजार महिलाओं के परिश्रम की सराहना करते हुए इसे 'विकसित भारत' की संकल्पना को साकार करने वाला कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं, सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा और बीमार पशुओं के उपचार हेतु 'मोबाइल वेटनरी यूनिट' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही, उन्होंने लखपति दीदियों और बायोगैस प्लांट के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन सरकार 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' और 'लखपति दीदी' जैसी योजनाओं के माध्यम से नारी सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि यह चिलिंग प्लांट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है, जहाँ 55 रुपये प्रति लीटर की दर से दुग्ध कलेक्शन कर सीधे किसानों और गौ-पालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी को प्रदेश की पाँचवीं ऐसी बड़ी कम्पनी बताया जो महिला उद्यमिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दुग्ध उत्पादन की इस प्रक्रिया में गुणवत्ता की पूरी गारंटी है और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली का नया मार्ग प्रशस्त हुआ है।

आजमगढ़ के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यह जनपद उपेक्षा का शिकार था, लेकिन आज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक स्तर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और फोरलेन कनेक्टिविटी ने लखनऊ व वाराणसी की दूरी को बेहद कम कर दिया है। उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना, आजमगढ़ एयरपोर्ट के विकास और तमसा गार्डन एन्क्लेव जैसी आवासीय योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज आजमगढ़ को उसकी वास्तविक पहचान और सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने गोवंश संरक्षण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और 'पी.एम. सूर्य घर योजना' के लाभ गिनाते हुए जनता से राष्ट्र निर्माण के इस महाभियान में जुड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर और कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

कृषि कायाकल्प से साकार होगा विकसित भारत का सपना:

मुख्यमंत्री ने किया छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस का भव्य शुभारम्भ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत 08 अप्रैल, 2026 को लखनऊ में 'विकसित कृषि-विकसित भारत/2047' के संकल्प के साथ आयोजित तीन दिवसीय 'छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस-2026' का विधि-विधान से शुभारम्भ किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के महासंगम को संबोधित करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट किया कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश का योगदान मात्र 11 प्रतिशत है, लेकिन अपनी उर्वरा शक्ति और जल संसाधनों के कारण यह प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21 प्रतिशत की बड़ी हिस्सेदारी रखता है। मुख्यमंत्री ने पिछले 09 वर्षों के प्रयासों की सफलता को साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में कृषि विकास की दर 08 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त हुई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 'उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना 2025-26' के अंतर्गत चयनित मेधावी वैज्ञानिकों को लाइफटाइम एचीवमेंट, विशिष्ट वैज्ञानिक, विशिष्ट महिला वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक और उत्कृष्ट पी.एच.डी. थीसिस जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया था। इसके साथ ही उन्होंने 'विकसित कृषि-विकसित उत्तर प्रदेश/2047' और 'उपकार कृषि प्रेरणा' सहित कृषि अनुसंधान पर आधारित कई महत्वपूर्ण पुस्तकों और पत्रिकाओं का विमोचन भी किया था।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की प्राचीन कृषि उद्यमिता का उल्लेख करते हुए कहा था कि जब विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 44 से 45 प्रतिशत थी, तब उसका आधार यहाँ का अन्नदाता किसान और उसकी उद्यमिता ही थी। उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में औपनिवेशिक शोषण और बंगाल के अकाल का जिक्र करते हुए वर्तमान वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे किसानों को केवल उत्पादक न रहने दें, बल्कि उन्हें उद्यमी के रूप में स्थापित करें। उन्होंने 'खेती की बात खेत पर' कार्यक्रम की सफलता पर चर्चा करते हुए बताया कि अब प्रदेश का किसान वर्ष में तीन फसलें ले रहा है और मक्के जैसी खेती से प्रति एकड़ एक लाख रुपये तक की बचत कर रहा है। मुख्यमंत्री ने गन्ने की मिठास को किसानों की समृद्धि से जोड़ते हुए जानकारी दी कि अब तक 02 लाख 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से गन्ना किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक बताते हुए कहा कि 122 चीनी मिलों में से अधिकांश मिलें अब किसानों को सात दिनों के भीतर भुगतान कर रही हैं। तकनीक और किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि निजी ट्यूबवेलों के बिजली बिल माफी के लिए सरकार ने 03 हजार करोड़ रुपये का भुगतान पावर कॉरपोरेशन को किया है। उन्होंने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने, निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु 7,700 गो-आश्रय स्थलों के निर्माण और किसानों के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था का विशेष उल्लेख किया था। मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों को 'लैब-टू-लैंड' के बजाय 'लैब-इन-लैंड' का नया मंत्र दिया और खेतों को ही प्रयोगशाला बनाने का आह्वान किया। इसके अलावा, उन्होंने असमय बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के अंतर्गत 5 लाख रुपये की सहायता राशि 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक और अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के बढ़ते उपयोग को कृषि के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य बताया था और आशा व्यक्त की थी कि तीन दिनों का यह मंथन अन्नदाता की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा।

बुन्देलखण्ड में रक्षा विनिर्माण को लगेंगे पंख: चित्रकूट में राडार और वायु रक्षा प्रणालियाँ बनाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में 08 अप्रैल, 2026 को उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड के अन्तर्गत 75 हेक्टेयर भूमि का आवंटन पत्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी0ई0एल0) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री मनोज जैन को सौंपा गया। चित्रकूट डिफेन्स नोड के व्यवस्थित एवं चरणबद्ध विकास की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल माना जा रहा है, जो प्रदेश में रक्षा विनिर्माण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के साथ-साथ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक आधार के विस्तार को नई गति प्रदान करने वाली सिद्ध हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल उत्तर प्रदेश को रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में एक सशक्त और विश्वसनीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने रेखांकित किया कि मध्य भारत में रणनीतिक रूप से स्थित चित्रकूट नोड अपनी उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और भौगोलिक अनुकूलता के कारण रक्षा उत्पादन का एक उभरता हुआ केन्द्र बन रहा है, जो आने वाले समय में निवेश, रोजगार सृजन और उच्च-प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार बनेगा।

मुख्यमंत्री ने परियोजना के विवरण साझा करते हुए बताया कि इस निवेश के अन्तर्गत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा लगभग 562.5 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक राडार एवं वायु रक्षा प्रणालियों के निर्माण हेतु एक उन्नत विनिर्माण इकाई स्थापित की जा रही है। यह इकाई न केवल रक्षा क्षेत्र में उच्च-प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन को सुदृढ़ करेगी, बल्कि प्रदेश में औद्योगिक दक्षता और तकनीकी क्षमताओं के विस्तार को भी नई दिशा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष बल दिया कि इसके परिणामस्वरूप 300 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जबकि सहायक एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन से स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चित्रकूट में इस उच्च-प्रौद्योगिकी इकाई की स्थापना से युवाओं का रोजगार हेतु पलायन रुकेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यह पहल 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को ठोस आधार प्रदान करते हुए रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन क्षमता को निर्णायक रूप से सुदृढ़ करेगी, जिससे आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। इस परियोजना से सहायक एवं एम0एस0एम0ई0 आधारित उद्योगों के विकास को गति मिलने और उन्नत तकनीकी सहयोग के नए अवसर सृजित होने की संभावना व्यक्त की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि चित्रकूट, जो अब तक अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के लिए विख्यात रहा है, अब रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में भी एक नई पहचान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। यह प्रस्तावित इकाई न केवल क्षेत्रीय विकास को नई गति देगी, बल्कि प्रदेश के संतुलित, समावेशी और बहुआयामी विकास के संकल्प को साकार करते हुए पारम्परिक विरासत और आधुनिक औद्योगिक प्रगति के बीच एक सशक्त समन्वय स्थापित करेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 07 अप्रैल, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

1- मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) पद्धति पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को विकसित कराए जाने हेतु द्वितीय चरण में, प्रारंभिक रूप से 54 बस स्टेशनों के स्थान पर अनुपयुक्त 06 बस स्टेशनों को छोड़ते एवं जनपद चंदौली को सम्मिलित करते हुए, कुल 49 बस स्टेशनों को विकसित कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

2- मंत्रिपरिषद ने डॉ. बी.आर. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

3- मंत्रिपरिषद ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाने के संबंध में 25 लाख टैबलेट क्रय किए जाने हेतु अंतिम बिड डॉक्यूमेंट पर अनुमोदन प्रदान किया है।

4- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत 08 प्रकरणों पर उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया है।

5- मंत्रिपरिषद ने जनपद गोरखपुर में 'उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय' की स्थापना तथा उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए 'उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश-2026' के आलेख को स्वीकृति प्रदान की है।

6- मंत्रिपरिषद ने जनपद बलिया में चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित जिला कारागार की 14.05 एकड़ (5.686 हे.) भूमि पर नवीन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

7- मंत्रिपरिषद ने भारत विभाजन के समय विस्थापित होकर जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर व बिजनौर में रह रहे शरणार्थी परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

8- मंत्रिपरिषद ने सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस में बस स्टेशन निर्माण के लिए ग्राम रतनपुर हुसैनपुर में खसरा संख्या-263, रकबा 10.012 हेक्टेयर भूमि में से 01 हेक्टेयर भूमि का परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क नामान्तरण/हस्तांतरण किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

9- मंत्रिपरिषद ने नरौरा, जनपद बुलंदशहर में बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला स्थापित किए जाने हेतु सिंचाई विभाग की भूमि तथा तहसील तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग की भूमि परिवहन विभाग को निःशुल्क नामांतरित/हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

10- मंत्रिपरिषद ने जनपद कन्नौज में विधानसभा क्षेत्र छिबरामऊ के अंतर्गत विकासखंड गुगरापुर में ग्राम चियासर के पास च्यवन ऋषि आश्रम के निकट चियासर घाट पर गंगा नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक निर्माण कार्य की संपूर्ण परियोजना, प्रश्नगत कार्य ई.पी.सी. मोड पर कराए जाने तथा उक्त कार्य की व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत 28899.22 लाख रुपये के व्यय प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया है।

11- मंत्रिपरिषद ने जनपद कुशीनगर में विधानसभा खड्डा के अंतर्गत नारायणी नदी के भैंसहा घाट पर दीर्घ सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक निर्माण कार्य की संपूर्ण परियोजना, प्रश्नगत कार्य ई.पी.सी. मोड पर कराए जाने तथा उक्त कार्य की व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत 70518.19 लाख रुपये के व्यय प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया है।

12- मंत्रिपरिषद ने जनपद शाहजहाँपुर में लिपुलेख भिंड मार्ग (राज्य मार्ग सं.-29) के चैनेज 468.750 से चैनेज 497.050 तक (लम्बाई 28.300 किमी) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की संपूर्ण परियोजना तथा उक्त कार्य की व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत 26670.09 लाख रुपये (दो सौ छियासठ करोड़ सत्तर लाख नौ हजार मात्र) का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

13- मंत्रिपरिषद ने पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के जनपद कानपुर देहात में पुनर्वासन हेतु लीज रेंट एवं पट्टे के प्रारूप के निर्धारण हेतु की गई कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया है।

14- मंत्रिपरिषद ने निजी क्षेत्र के अंतर्गत मेट्रो विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना हेतु प्रायोजक संस्था सनहिल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को संचालन का प्राधिकार निर्गत किए जाने तथा 'उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026' के प्रतिस्थानी विधेयक को विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर उसे राज्य विधान मंडल में पुरःस्थापित/पारित कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

उत्तर प्रदेश ई संदेश